प्राकृतिक संसाधन नियोजनः कृषक आय बढोतरी में सहायक

रजनी जैन, सोनिया चौहान एवं मंगल सिंह चौहान
भाकृअनुप– राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
*संवादी लेखक का ई–मेलः sonia.chauhan@icar.gov.in

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। स्वतन्त्रता के सात दशक बाद भी लगभग 60 प्रतिशत आबादी अपनी जीविकापार्जन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। समय परिवर्तन के साथ भारतीय कृषि ने भी कई परिवर्तन देखे है, परन्तु किसानों की दशा मे कुछ खास बदलाव नही आया है। भारतीय सरकार, अनुसंधान कर्मी और अर्थ शास्त्री किसानों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते रहते है और उनकी स्थिति में सुधार को कार्येरत है। मौजूदा भारतीय सरकार भी किसानों की दशा तथा आय बढ़ाने को प्रयासरत है। इसी दिशा में 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अंतर्गत अनेक योजनाएँ जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना आदि को शामिल किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने को अनेक तकनीकियों और प्रणालियों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। जल एवं मृदा उपयोग नियोजन भी इसी का हिस्सा है।

मृदा नियोजन

भूमि उपयोग नियोजन पृक्रिया मे सर्वप्रथम मृदा की जांच कर उसकी प्रकृति को देखा जाता है कि मृदा अम्लीय, क्षारीय या लवणीय है। फिर इस बात को समझा जाता है कि किस प्रकार के पोषक तत्वो को मिलाने से इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर मृदा अम्लीय है तो मृदा में चूना मिलाने से उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अगर मृदा क्षारीय है तो उसमे कई पोषक तत्वो जैसे लोहा, जिंक कॉपर, मैगनिज आदि की कमी हो सकती है जिसे जिप्सम और जैविक खाद मिलाकर पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार मृदा की प्रकृति को जानकर उसमे किस फसल की पैदावार ज्यादा हो सकती की जानकारी भी किसानों को दी जाती है। इस दिशा मे सरकार ने फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभ आरंभ किया। इस योजना के तहत हर किसान को उसके खेत की मिट्टी की जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है जिससे किसान अपनी मिट्टी को जानकर उसमे आवश्यक सुधार कर सकते है। मृदा में पोषक तत्वो की कमी और अधिकता की जानकारी होने पर किसान भाई मृदा विशेषकों से अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने की सलाह ले कर अधिक उपज ले अपनी आय बढ़ा सकते है। इससे एक तरफ खेती मे प्रयोग होने वाले अनावश्यक रसायनिक खाद पर अंकुश लगेगा जिससे मृदा और जल का स्वास्थ्य बना रह पाएगा और दूसरी तरफ उत्पाद सामग्री पर होने वाले खर्चे मे भी कमी आयेगी । मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत दस करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बाटें जा चुके है।

जल नियोजन

प्राकृतिक संसाधन नियोजन के अंतर्गत केवल मृदा का ही नही अपितु जल के उचित नियोजन के सुझाव भी किसानों को बताए जाते है। आईआईटी द्वारा किया गया एक अधध्यन दिखाता है कि वर्ष 2005 से 2013 तक भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों (असम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल) में उपयोग योग्य भूजल मे काफी गिरावट दर्ज की है जिसके फलस्वरूप भयंकर सूखा, खाद्यान संकट और पीने योगय जल की कमी का खतरा बढ़ रहा है। अधिक खाद्यान उत्पादन में अत्यधिक भूजल के प्रयोग के कारण भूजल स्तर खतरे के निशान तक पहुँच गया है इसलिए समय की मांग है कि कौन सी फसल मे कब–कब और कितना पानी देने की आवश्कता है के बारे में भी बताया जाता है। "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" अर्थात हर बूंद पर ज्यादा फसल की नीति अपनाने की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सिंचाई के नवीनम तरीके जैसे फव्वारा सिंचाई और बूंद–बूंद सिंचाई के साथ ही सरकार द्वारा मिलने वाली सबसिडी का ज्ञान भी किसानों को दिया जाता है। कुछ प्रदेशों मे धान– गेहूं फसल

चक्र के कारण भू–जल स्तर चिंतनीय अवस्था में पहुँच गया है। घटते जल स्तर को ध्यान मे रखते हुए कम जल खपत वाली फसलों का विकल्प भी सुझाया जाता है।

समेकित कृषि

किसानो की आय मे बढ़ोतरी के लिए समेकित कृषि पर भी जोर दिया जाता है। इसमें एक फसल पर निर्भर न रहते हुए अंतर फसले लेने पर जोर दिया जाता है। इससे अगर एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है। इस योजना मे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसानो को सालभर रोजगार मिलता रहे इसलिये कृषि के साथ–साथ मवेशी पालन, वानिकी, बागवानी तथा मत्स्य पालन को समायोजित करने के सुझाव भी मुहाएया कराये जाते हैं। खेती के साथ किन लघु उद्योगो को किसान अपना सकते हैं और खेत के पास ही उपज (उत्पाद) को संसाधित कर उसका मूल्य संवर्धित कर अधिक आय कमा सकते है। इस योजना मे किसानों को सामाजिक तौर पर अपनाये जा सकने वाले और आर्थिक तौर पर प्रभावी सुक्षाव दिये जाते हैं। भारत के कई गावों के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे है तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

कटाई उपरांत प्रसंस्करण एवं बाजार ज्ञान

इस योजना मे केवल प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन के बारे में ही नही बताया जाता अपितु अधिक मुनाफे के लिए विभिन्न मंडियों के भावों की जानकारी भी दी जाती है। "जो बिके वो उगे" का ज्ञान भी किसानों के साथ साझा किया जाता है। इसके साथ ये बताया जाता है की किसान खेती के साथ साथ कौन कौन से लघु उद्योग अपनाकर अपना मुनाफा बढ़ा सकते है। जैसे दलहन फसलों के साथ ही उन्हे साफ कर पेकिंग का काम किया जा सकता है। कई तरह के अचार बना कर उनकी बिक्री की जा सकती है जो निश्चित तौर पर फलो सब्जियों के नुकसान को तो कम करेगा ही, रोजगार बदने मे भी मददगार होगा।

जानकारी स्रोत

इस दिशा मे किसानों को मदद देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न संस्थान काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी हेल्पलाइन का उपयोग किसान भाई सहज ही कर सकते है। भूमि उपयोग नियाजन और फसलों से संबन्धित जानकारी किसान आईसीएआर के 109 संस्थानों से प्राप्त कर सकते है। ये संस्थान विभिन्न फसलों, मवेशी पालन, वानिकी, बागवानी और मत्सय पालन से संबंधित शोध करते है। मृदा के बारे में सभी तरह की जानकारी और सुझाव राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग संस्थान से लिए जा सकते है। इसके अलावा राज्य तथा केंद्र कृषि विश्वविद्यालय कृषि आधारित कोर्सेस कराते है और किसानों को जागरूक करते है। हर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों की हर तरह से सहायता करते है किसान भाई वहाँ से भी मदद और जानकारी ले सकते हैं।

निष्कर्ष

किसान जो भारतीय अर्थ वयवथा की रीढ़ माने जाते रहे हैं। अगर वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो अर्थव्यवस्था भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। इसके लिए आवश्यक है कि एक तरफ सीमित प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जाए और उनके अत्यधिक दोहन पर अंकुश लगे और दूसरी तरफ किसानों की आय मे बढोतरी हो। मृदा तथा जल के नियोजन से दो तरफा लाभ लिया जा सकता है। आवश्यकता है किसान मृदा की जांच करवाएं, उस समझे और कृषि विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन करे तो निश्चित तौर पे उनकी आय मे बढोतरी संभव है।

अपनी मातृभाषा बंगला में लिखकर मैं बंगबन्धु तो हो गया, किन्तु भारतबन्धु मैं तभी हो सकूँगा जब भारत की राष्ट्रभाषा में लिखूंगा ।

– बंकिम चन्द्र चट्टोपाय